बिहार में उच्च शिक्षा की दशा और दिशा

डॉ. बासुकी नाथ चौधरी,
एसोसिएट प्रोफेसर,
पी.जी.डी.ए.वी. कॉलेज (सांध्य),
दिल्ली विश्वविद्यालय

सार

काफी समय से बिहार गलत कारणों से समाचार में रहा है। परीक्षाओं में कदाचार की तस्वीर कई बार दिखाई गयी है। लेख लिखे गये हैं और विदेशों में भी इस पर चर्चा होती है। मैं स्वयं उच्च शिक्षा में कार्यरत हूँ, इसीलिए मैंने बिहार में उच्च शिक्षा की दशा और दिशा पर कार्य करने का निर्णय किया। व्यथित तो तब हुआ जब इसी सोच को ध्यान में रखे हुए बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के नाम पर स्थापित महाविद्यालय (श्री कृष्ण रामरुचि महाविद्यालय) पहुँच गया। यह बिहार के शेखपुरा जिला के बरबीघा में अवस्थित है। यह तिलका माँझी, भागलपुर विश्वविद्यालय का अंगीभूत कॉलेज है। चाहत यह भी थी कि बच्चों के साथ एक–दो दिन क्लास में अपने विषय से जुड़े कुछ मुद्दों पर बातचीत भी करेंगे। व्यथित करने वाली निराशा हाथ लगी। करीब 2 बजे दिन में छात्र और शिक्षक दोनों नदारद थे।

लगभग 3800 छात्र, 11 शिक्षक और कई विषयों में एक भी शिक्षक नहीं। शिक्षकों से ज्यादा ऑनर्स विषयों के लिए कॉलेज। खैर, शाम में खेल के मैदान में 20–25 बच्चों से मुलाकात हुई। अर्थशास्त्र के एक शिक्षक से भी मुलाकात हुई। वहाँ जो बात हुई, शर्मिन्दा करने वाली है और उसकी चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन इस प्रकरण ने मुझे प्रेरित किया कि कम–से–कम, इसी विश्वविद्यालय के एक और कॉलेज को देखा जाय और मैं मुंगेर जिले के बड़हिया अवस्थित बी. एन.एम. कॉलेज पहुँच गया। स्थिति और भी बदतर। 2200 के आस–पास छात्र, 12 ऑनर्स के विषय और 4 शिक्षक। अनुपस्थित छात्र और दयनीय हालत। इन परिस्थितियों ने मेरे इरादों को और मजबूत किया और मैंने काम शुरू कर दिया। जो भी आँकड़े इसमें हैं, भारत सरकार के विभिन्न एजेंसियों के आँकड़े हैं और उसमें उद्धृत भी किया गया है।

तो आइये, पहले हम समझने का प्रयास करें कि शिक्षा क्या है? उच्च शिक्षा का अर्थ क्या है? और समाज के लिए उच्च शिक्षा का महत्व क्या है?

ऋग्वेद के नासदिया सूत्र में कहा गया है – ''सा विद्या या विमुक्तये'' अर्थात् जो हमें पूर्वाग्रह, जड़ता, रूढ़ियों और पदार्थों की उपासना से मुक्त करे। यह आत्मज्ञान है जो आत्मसंयम से होता है। यही शिक्षा है।

गांधी जी की राय में शिक्षा एक ऐसे व्यक्ति की संरचना करता है जिसके आचरण में अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, शील, संतोष, तप एवं स्वाध्याय हो और जीवन को ऐसा बना दे जहाँ सत्यम्, शिवम् और सुन्दरम् की गूँज सुनाई देती हो।

विवेकानंद ने ऐसे शिक्षा की वकालत की जो पश्चिमी वैज्ञानिक खोज एवं रूढ़ि मुक्त भारतीय संस्कार का योग हो एवं मनुष्य में सेवा एवं सहिष्णुता का भाव पैदा करता हो।

प्लेटो भी मानव के नैतिक एवं बौद्धिक, दोनों के विकास के लिए शिक्षा पर ही बल देते हैं। कुछ शिक्षाविद् शिक्षा को साध्य प्राप्ति का साधन समझते हैं तो कुछ उसे साध्य ही मानते हैं।

शिक्षा अर्थात् एडुकेशन शब्द लैटिन भाषा के शब्द एडुकेयर से निःशक्त है जिसका अर्थ है व्यक्ति की छिपी हुई प्रतिभा को प्रशिक्षण के माध्यम से समग्रता में उभारना। कुल मिलाकर शिक्षा वह प्रक्रिया है जो तात्कालिक समस्याओं के समाधान हेतु प्रशिक्षण और तकनीकी ज्ञान से नागरिकों को इस तरह से तैयार करें कि वह सामाजिक परिवर्तन का वाहक हो तभी तो सैम पित्रोदा कहते हैं कि धन उत्पत्ति, सम्पन्नता, वैश्विक अर्थव्यवस्था विकास की शक्ति सिर्फ शिक्षा के माध्यम से प्राप्त हो सकती है।

उच्च शिक्षा क्या है?

माध्यमिक शिक्षा के बाद कॉलेज एवं विश्वविद्यालय स्तर पर दी जाने वाली शिक्षाएँ उच्च शिक्षा की श्रेणी में आती है। यद्यपि, पॉलिटेक्निक एवं व्यावसायिक संस्थायें आवश्यक रूप से उच्चतर–माध्यमिक शिक्षा नहीं है फिर भी उसे उच्च शिक्षा में शामिल किया जाता है। उच्च शिक्षा को सामान्यता दो स्रोतों में बाँटा गया है – एक, जो गैर–तकनीकी ज्ञान का संवर्द्धन करता है और दूसरा जो तकनीकी माध्यम से मानव–पूँजी का निर्माण करता है। केन्द्रीय विश्वविद्यालय, प्रांतीय विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय पहले स्तर के लिए जबकि तकनीकी संस्थायें IITs, IIMs, मेडिकल कॉलेज ICAR आदि तकनीकी जिम्मेदारी निभाते हैं। आज की दुनिया को देखते हुए इसमें दो राय नहीं कि समाज को सबसे पहले पर्याप्त मात्रा में मानव पूँजी की जरूरत है। यह सर्वविदित है डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर आदि की कमी एवं उसके कारण पड़ने वाले दुष्प्रभावों की मार समाज झेल रहा है। वस्तुतः मानव–पूँजी की अवधारणा शिक्षा एवं स्वास्थ्य को श्रम की उत्पादकता बढ़ाने का माध्यम मानती है।

समाज के लिए इसकी उपयोगिता :

निम्न रूप में इसकी उपयोगिता दर्शायी जा सकती है–

1. शिक्षित लोग सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति ज्यादा सजग होते हैं। यह सजगता प्रजातंत्र का मुख्य आधार है।
2. शोध से पता चलता है कि एक प्रतिशत साक्षरता दर बढ़ने से जीवन प्रत्याशा दो वर्ष बढ़ जाता है और यही ज्ञान जनसंख्या विस्फोट को रोक सकता है।
3. शिक्षा स्वास्थ्य की ओर सजगता बढ़ाता है और स्वास्थ्य श्रमशक्ति की प्रभावोत्पादकता को बढ़ाता है।
4. यदि बाजार की दृष्टिकोण से देखे तो राजनैतिक स्थिरता, समुचित कानूनी व्यवस्था से चलाया जा रहा शासन निवेश के लिए उचित माहौल पैदा करता है।
5. शिक्षा केवल कार्यक्षमता बढ़ाने मात्र का साधन नहीं है यह जनसाधरण की सहभागिता को व्यापक बनाने तथा व्यक्ति एवं समाज की समग्र गुणवत्ता के उन्नयन का एक प्रभावी उपकरण भी है।

इस शोध प्रपत्र में उच्च शिक्षा की दशा भारत मे विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में उसकी समीक्षा का आंकलन किया गया है, जिसके आँकड़े मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा लिए गये हैं।

इस शोध पत्र में मैंने बिहार का अध्ययन करने के लिए चार और राज्यों को लिया। दो राज्य जो उसकी आबादी की तुलना में लगभग एक दहाई है और दो राज्य जो लगभग उसकी जनसंख्या के करीब है। सम्बन्धित राज्यों के जनसंख्या के तुलनात्मक अध्ययन को निम्न सारणी में देख सकते हैं–

जनसंख्या विवरण

क्रम सं.	राज्य	जनसंख्या
1.	बिहार	10,3804697
2.	आंध्र प्रदेश	84665533
3.	तमिलनाडू	72138958
4.	हिमाचल प्रदेश	6856509
5.	दिल्ली	16753235

स्रोत–जनगणना 2011

राज्यों में कार्यरत विश्वविद्यालयः

निम्न राज्यों में विश्वविद्यालयों की संख्या इस प्रकार हैः–

क्रम	विश्वविद्यालय	आंध्र प्रदेश	बिहार	तमिलनाडू	दिल्ली	हिमाचल प्रदेश
1.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय	3	1	2	4	1
2.	केन्द्रीय मुक्त विश्वविद्यालय	–	–	–	1	–
3.	राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएँ	2	2	5	3	–
4.	प्रांतीय विश्वविद्यालय	31	14	20	5	3
5.	प्रांतीय मुक्त विश्वविद्यालय	1	1	1	–	–
6.	प्रांतीय निजी विश्वविद्यालय	–	–	–	–	8
7.	डीम्ड विश्वविद्यालय (सरकारी)	2	1	–	9	–
8.	डीम्ड विश्वविद्यालय (निजी)	5	–	27	1	–

स्रोत – UGC 2013

उपर्युक्त आंकड़ों द्वारा यह समझाने का प्रयास किया गया है कि उपरोक्त राज्यों में उच्च शिक्षा की कितनी और किस प्रकार की संस्थाएँ कार्यरत हैं।

राज्यों में प्रति लाख कॉलेजों की संख्या

क्रम	शीर्षक	आंध्रप्रदेश	बिहार	तमिलनाडू	हिमाचल प्रदेश	दिल्ली
1.	कॉलेजों की संख्या	4801	665	2499	186	295
2.	प्रतिलाख जनसंख्या पर कॉलेज	48	6	33	9	38
3.	प्रति कॉलेज औसत नामांकन	473	1688	811	1081	441
4.	साक्षरता दर	67.02%	61.8%	80.09%	86.2%	82.8%
5.	जनसंख्या	8.45Cr	10.42 Cr	7.21 Cr	1.67 Cr	68.64 Lakh
6.	**शीर्षक**	**आंध्रप्रदेश**	**बिहार**	**तमिलनाडू**	**हिमाचल प्रदेश**	**दिल्ली**
7.	कॉलेजों की संख्या	4801	665	2499	186	295
8.	प्रतिलाख जनसंख्या पर कॉलेज	48	6	33	9	38

स्रोत– UGC 2013

उपरोक्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि मामला चाहे कॉलेज की संख्या का हो या प्रति कॉलेज बच्चों के नामांकन का हो या फिर साक्षरता दर का हो, बिहार इन छोटे राज्यों के सामने भी कहीं नहीं टिकते।

यदि हम मानित (Deemed) विश्वविद्यालय की तुलना करें तो दिल्ली में 9 मानित विश्वविद्यालय हैं और बिहार में केवल एक। प्रति कॉलेज नामांकन बिहार की तुलना में एक तिहाई है। स्वाभाविक है कि वहाँ के बच्चों को ज्यादा सुविधा और ज्यादा ध्यान मिलेगा जिससे उनका विकास बेहतर होगा ही।

राज्यवार नामांकन (विभिन्न पाठ्यक्रमों में)

राज्य	Ph.D.	M.Phil.	PG	UG
आंध्र प्रदेश	7915	1176	432639	2271410
बिहार	2226	Nil	92091	1078676
दिल्ली	8130	5030	99182	641864
हिमाचल प्रदेश	881	415	23682	138307
तमिलनाडू	13216	13606	496447	2205385

स्रोत– UGC 2013

यदि इन आँकड़ों को विश्लेषित किया जाये तो PG में बिहार के छात्रों की संख्या 92091 है तो दिल्ली में 99182 है जबकि UG के स्तर पर बिहार का 1078676 है तो वहीं दिल्ली का 641864। इससे साफ है कि स्नातक से पर–स्नातक तक जाने में बिहार में 90 प्रतिशत छात्र असफल रहते हैं जबकि दिल्ली जैसे छोटे प्रांतों में UG में बच्चों की संख्या 6.41 लाख है, PG में लगभग एक लाख हैं। यदि हम केवल दिल्ली से तुलना करें तो Ph.D. के छात्रों की संख्या बिहार के Ph.D. के छात्रों की तुलना में तीन गुणा से भी ज्यादा है। लगभग प्रत्येक राज्यों के विश्वविद्यालयों में M.Phil. पाठ्यक्रम चलता है बिहार में किसी विश्वविद्यलय ने अभी तक इसकी शुरुआत भी नहीं की है। इसका दो दुष्परिणाम तुरंत दिखाई देता है:–

1. कॉलेज में असिसटेण्ट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए ए.पी. आई 100 के अंक पर कम–से–कम 60 अंक प्राप्त करने वाले को योग्य माना जाता है। M.Phil. का 10 अंक निर्धारित है। बिहारी छात्र इस दौर में हर जगह पिछड़े रहते हैं।
2. यदि नौकरी में आ भी जाए तो भी वेतन में उसे दो इनक्रीमेट का घाटा होता है और यह अवकाश प्राप्त होने तक सतत् घाटे की स्थिति है। अब पॉलिटेक्निक और नर्सिंग संस्थाओं में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास द्वारा दिए गए आँकड़ों को मानें तो निम्न आँकड़े सामने आते हैं:–

पॉलिटेक्निक और नर्सिंग संस्थाएँ

राज्य	पॉलिटेक्निक संस्थाएँ	नर्सिंग संस्थाए
आंध्र प्रदेश	194	654
बिहार	20	14
दिल्ली	36	17
हिमाचल प्रदेश	34	24
तमिलनाडू	470	122

स्रोत– मानव विकास मंत्रालय

केवल यदि इन संस्थानों और इसके नामांकित बच्चों का विश्लेषण किया जाय तो साफ है कि दिल्ली और हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्यों की तुलना में भी बिहार कम नर्सिंग स्टाफ पैदा कर रहा है। आंध्र प्रदेश जो लगभग 80 हजार से ऊपर नर्सिंग स्टाफ उत्पन्न करता है, बिहार मात्र 2000 के आसपास तैयार कर पाता है। निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि मामला पॉलिटेक्निक का हो या नर्सिंग का बिहार रोजगार के अवसर ही उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। साथ ही यदि दिल्ली एवं हिमाचल की तुलना में कम स्टाफ तैयार करते हैं तो राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवा की आशा कैसे करें? यह भी संज्ञान लेने योग्य बात है कि प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ स्वाभाविक तौर पर अपने परिवार के सदस्यों को ज्यादा स्वस्थ रखेगा और उसका इलाज पर होने वाला खर्चा कम

होगा और गाढ़ी कमाई से अर्जित किए गये धन को ज्यादा बचा पाएगा। इतना ही नहीं केरल और दक्षिण के कई अन्य राज्यों के प्रति व्यक्ति आय में इस कारण से बहुत ज्यादा इज़ाफा भी हुआ है।

शिक्षकों के आंकड़ेः

अब यदि शिक्षकों की संख्या की बात की जाये तो निम्न आँकड़े सामने हैंः–

राज्य	प्रोफेसर	एसोसिएट प्रो.	असिस्टेंट प्रो.	छात्र शिक्ष अनुपात
आंध्र प्रदेश	14371	19694	123771	13:1
बिहार	2565	4949	19349	39:1
दिल्ली	2746	4755	8157	16:1
हिमाचल प्रदेश	887	1233	5848	19:1
तमिलनाडू	15973	18741	135551	14:1

स्रोत : All India Survey on Higher Education 2012-13

बिहार विश्वविद्यालयों की स्थितिः

ये आँकड़े ऐसे हैं जो स्वयं चीख–चीखकर अपनी कहानी कहते हैं, विश्लेषण की आवश्यकता नहीं। अब छोड़िए तुलनात्मक अध्ययन को और आइये बिहार के एक–एक विश्वविद्यालय की विशेषताओं पर गौर करें। यह 2011–2012 के सर्वे पर आधारित है–

क्रम संख्या		कॉलेज की संख्या	
1. ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा			
Constituent College		43	
Affiliated College		50	
स्थायी शिक्षकों की संख्या		110	
		क्षमता	**प्रवास**
छात्रावास की संख्या			
	3 (छात्र)	274	102
	1 छात्रा)	68	00
2. जयप्रकाश विश्वद्यालय, छपरा			
No. of Affiliated College		26	
No. of Constituent College		21	
स्थायी शिक्षकों की संख्या		71	
छात्रावास की संख्या		NIL	
3. भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा			
No. of Affiliated College		42	
No. of Constituent College		27	
स्थायी शिक्षकों की संख्या		59	
		(केवल छात्राओं के लिए – 1)	
छात्रावास की सुविधा			
		क्षमता 40	प्रवास 00
5. मगध विश्वविद्यालय, बोध गया			
Constituent College		44	
Affiliated College		98	
स्थायी शिक्षकों की संख्या		107	
		क्षमता	**प्रवास**
छात्रावास की संख्या			
	6 (छात्र)	1200	Nil
	2 (छात्रा)	400	400

क्रम संख्या		कॉलेज की संख्या	
6. वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा			
Constituent College		17	
Affiliated College		16	
स्थायी शिक्षकों की संख्या		94	
		क्षमता	**प्रवास**
छात्रावास की संख्या			
	1 (छात्र)	60	00
	00 (छात्रा)	00	00
7. बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर			
Constituent College		7	
स्थायी शिक्षकों की संख्या		32	
8. राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर			
Constituent College			5
स्थायी शिक्षकों की संख्या		224	
		क्षमता	**प्रवास**
छात्रावास की संख्या			
	5 (छात्र)	990	585
	3 (छात्रा)	355	238

स्रोत–UGC 2011

अब मैं आपको 2013 में कॉपीराइट के तहत् UGC ने जो आँकड़े दिया है उस आँकड़े को प्रस्तुत करता हूँ और मानव–संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दिया गया आँकड़ा और UGC द्वारा दिए गए आँकड़ो का यदि तुलनात्मक अध्ययन करें तो एक राई है तो दूसरा पहाड़। किस पर विश्वास करें, कहना मुश्किल है, यदि सरजमीं पर चले जाएं तो एक तीसरा आँकड़ा ही उभरकर सामने आता है। आइये प्रत्येक विश्वविद्यालय का अलग–अलग चित्र प्रस्तुत करें–

विश्वविद्यालय का नाम	विभिन्न कॉलेजों, अध्ययन केन्द्र, क्षेत्रीय केन्द्र, विभाग, पी.जी केन्द्र आदि की	शिक्षकों की कुल संख्या	शिक्षकों की औसत संख्या	कुल शोधार्थी छात्रों का प्रतिशत

	कुल संख्या			
ललित नारायण मिथिला, दरभंगा	159	1915	12..04	1.2
जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा	19	812	7.44	0.89
बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर	13	1875	144.2	0.26
बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा	88	1004	11.40	अनुपलब्ध
नालंदा खुला विश्वविद्यालय, पटना	143	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया	169	1775	10.50	0.90
राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर	44	664	15.09	1.79
वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा	107	2522	23.57	अनुपलब्ध

यदि इसे विश्लेषित किया जाये तो स्थिति वही ढाक के तीन पात है जो उपर्युक्त विश्लेषित बाबा साहब अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय जैसा ही दिखता है। कुल मिलाकर भगवान ही मालिक है।

बिहार में उच्च शिक्षा के समक्ष चुनौतियाँः–

1. **माँग आपूर्ति में विसंगतियाँ** : फरवरी 2014 में एक सेमिनार में बोलते हुए तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री कपिल सिब्बल ने कहा कि पूरे भारत में 12.4 प्रतिशत बच्चे उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं और 2020 तक यदि 800–1000 विश्वविद्यालय और 4000 महाविद्यालय खोले जाए तभी निर्धारित 30 प्रतिशत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। यह स्थिति सम्पूर्ण भारत की है। जनसंख्या के आधार पर और अलग–अलग राज्यों की तुलना करने से जो खाईं हमें दिखती है उससे लगता है कि कम–से–कम 400 महाविद्यालयों और 40 विश्वविद्यालय यदि बिहार में खोले जाएं तभी यह दूरी समाप्त हो पाएगी।
2. **गुणवत्तापरक शिक्षा** :– प्रतिस्पर्धी वैश्विक बाजार में मानव–पूँजी की गुणवत्ता ही आपको प्रतिष्ठापित करती है। फिलहाल दिए गए हाल के सरकारी आँकड़ों के आधार पर दो–तिहाई भारतीय महाविद्यालय एसं विश्वविद्यालय निम्न–स्तरीय हैं। रिपोर्ट में बिहार की चर्चा निम्नतम् स्तर पर है।
3. **शोध एवं विकास** : शोध एवं विकास उच्च शिक्षा के वाहक हैं। बिहार में शोध संस्थानों की अत्यंत कमी है और जो है भी उसका विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों से सीधा सम्पर्क नहीं है।

शिक्षकों की कमी :– भारत के आँकड़ों के अनुसार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में 35 प्रतिशत तक शिक्षकों की कमी है। IIMs में 25 प्रतिशत NITs में 33.33 प्रतिशत और मानव संसाधन मंत्रालय के अधीन अन्य केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थानों में 35.1 प्रतिशत शिक्षक नहीं हैं। अब बिहार में शिक्षकों की संख्या के जो आँकड़े प्रस्तुत किए गए हैं वह न केवल दयनीय है वरन् मृत समाज का अहसास करवाता है।

शिक्षकों की अनुपस्थिति :– संख्या इतनी कम है और छात्र इतने अधिक हैं कि कक्षाएँ नहीं लग पाती। धीरे–धीरे शिक्षकों और छात्रों दोनों का आना बंद हो जाता है।

सुझावः–

1. नियामक निकायों का अधिकार के साथ–साथ उत्तरदायित्व भी तय करना होगा और पदाधिकारियों के लिए भी दण्ड की व्यवस्था हो।
2. शिक्षा पर व्यय को बढ़ाते हुए आधारभूत संरचना को मजबूत करना होगा।
3. निजी विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा और जो लोग खोलना चाहें उन्हें कर–लाभ देने की जरूरत हैं तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति नियत समय हेतु तुरंत किया जाय।
4. सत्र को आवश्यक रूप से नियमित और इसके लिए बच्चों के अलग से क्लास की व्यवस्था हो।
5. तीन तटस्थ शिक्षकों की कमेटी हो, जो वास्तविक तस्वीर को सामने ला सके।

अंततः निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि बिहारी छात्रों में तीक्ष्णता की कमी नहीं है, धार देने की जरूरत है और यदि विसंगतियों को दूर नहीं किया गया तो कदाचार को भी नहीं रोका जा सकता है। चाहे चर्चा कितनी भी कर लें और नैतिकता के धरातल पर उसकी भर्त्सना भी।

उपसंहारः–

अपना अध्ययन पूरा करने के बाद मैंने सोचा कि यह आलेख बिहार सरकार और भारत सरकार तक पहुँचाया

जाय। इसी संदर्भ में मैंने शिक्षाविद् सांसद श्री अरुण कुमार (जहानाबाद), केन्द्रीय शिक्षा राज्यमंत्री, श्री उपेन्द्र कुशवाहा और बिहार सरकार के मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी को मुख्यमंत्री श्री नीतिश कुमार की उपस्थिति में सौंपा। राम जाने, उन लोगों ने कोई कार्यवाही की या नहीं लेकिन सुखद यह है कि बिहार में असिसटेण्ट प्रोफेसर की नियुक्तियाँ शुरू हो गयी हैं। मैं भी कुछ ऐसे मित्रों को जानता हूँ जो दिल्ली विश्वविद्यालय में अस्थायी तौर पर पढ़ा रहे हैं की नियुक्ति स्थायी तौर पर हुई है। आशा की जानी चाहिए कि बिहार में उच्च शिक्षा की दिशा और दशा में परिवर्तन होगा। पक्का है कि यदि भारत को विश्वगुरु बनने का सपना साकार करना है तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाना ही होगा जो जय प्रकाश जी के आन्दोलन के समय से ही मजाक रह गया है।

संदर्भ–सूची

- भारतीय जनगणना, 2012
- मनित विश्वविद्यालय सूची, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
- उच्च शिक्षा, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, भारत सरकार, 2011
- राज्य सरकार विश्वविद्यालय सूची, 2011
- सांख्यिकी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

** बिहार के कुछ विश्वविद्यालयों में किया गया प्रत्यक्ष सर्वे

** उपरोक्त वर्णित विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी, शोधार्थी और प्रोफेसर के साथ प्रत्यक्ष साक्षात्कार द्वारा